RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –I GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - POLITICAL

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. ऑक्वर्थ समिति क्या हैं ?

उत्तरः–1920 में गठित 10 सदस्यीय समिति जिसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। (1924में)

2. उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं ?

उत्तरः–13 दिसम्बर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत भावी भारत का आदर्श चित्रण जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, वैश्विक शांति में योगदान को महत्व दिया गया, यही बाद में प्रस्तावना में रूपान्तरित हुआ ।

3. अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' कितने प्रकार से संभव हैं ?

अनुच्छेद 368 → संविधान संशोधन की 2 विधियाँ

- **विशेष बहुमत** — उदाहरणः– नीति निदेशक तत्वों में संशोधन (उपस्थित व मतदान करने वालों का $^{2}/_{3}$ एवं कुल सदस्यों का 50%+1)
- विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों की सहमति — उदाहरणः– 7वीं अनुसूची में परिवर्तन

4. न्यायिक पुनरावलोकन व न्यायिक सक्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए ?

उत्तरः–

न्यायिक पुनरावलोकन	न्यायिक सक्रियता
☞ कानून/आदेशों की समीक्षा व वैधता की जाँच ☞ अनुचित को रोकने के उद्देश्य से ☞ मूल अधिकारों का संरक्षण ☞ उदाहरण–NJAC को विधि शून्य घोषित करना।	☞ जब न्यायपालिका संविधानवाद के दायरे से विस्तृत हो सार्वजनिक नीति पर विचार प्रकट करें। ☞ उचित के क्रियान्वयन के उद्देश्य से ☞ नीति निदेशक तत्वों में प्रेरित ☞ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश

5. 'डायस्पोरा' शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता हैं ?

उत्तरः–डायस्पोरा शब्द विदेश में प्रवासन करते हुए भी अपने देश की संस्कृति से जुड़ाव रखने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता हैं।

6. राज्य निर्माण व राष्ट्र निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए ?

उत्तरः–

राज्य निर्माण	राष्ट्र निर्माण
☞ भौतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण ☞ योजनाओं, बजट व लोक कल्याण के प्रावधान से संबंधित ☞ उदाहरण–आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण	☞ भावनात्मक एवं सांस्कृतिक एकीकरण ☞ राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व राष्ट्रीय समर्पण के प्रावधान से संबंधित ☞ उदाहरण–आत्मसातीकरण, सामासिक संस्कृति, विविधता में एकता

7. सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य हैं ?

उत्तरः– एक धार्मिक समूह के द्वारा अपनी धार्मिक श्रेष्ठता एवं अन्यों की धार्मिक निकृष्टता का भाव एवं तनाव की मनोदशा रखना ही साम्प्रदायिकता हैं। धर्म सांप्रदायिक नहीं है, किन्तु सांप्रदायिकता धर्म पर आधारित होती है।

8. नक्सलवाद पर नियंत्रण के उपाय बताइयें?

☞ नक्सल क्षेत्रों का समग्र विकास (आधारभूत संरचना, रोजगार, शिक्षा इत्यादि) हो ।

☞ भूमि अधिग्रहण में पर्याप्त मुआवजा एवं पुनर्वास का प्रावधान हो, पर्याप्त राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।

☞ सीमा प्रबंधन सुदृढ़ किया जाये, संघ (आतंरिक सुरक्षा) व राज्य (कानून व व्यवस्था) में समन्वय बढ़ाया जाये।

☞ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से शासन के रचनात्मक उद्देश्य बताये जाये।

9. अलगाववाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता हैं ?

उत्तरः–किसी एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपनी पृथक पहचान (नृजातीय, नस्लीय, भाषागत, धर्म) के आधार पर गैर सम्बद्धता की भावना रखना ही अलगाववाद हैं।

10. उत्तर-पूर्वी भारत में अलगाववाद के प्रमुख कारण बताइयें ?

☞ उत्तर-पूर्वी भारत की भौगोलिकता, दूरी व नृजातीय समूहों की बहुलता

☞ भारत के राजनैतिक-प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टताओं में हस्तक्षेप

☞ पड़ौसी राष्ट्रों से प्राप्त सहायता व राजनैतिक दलों द्वारा मतों का ध्रुवीकरण

11. राष्ट्रीय मुकदमा नीति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए ?

उत्तरः– जी.आई.वाहनवती द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया, अधिकांश मुकदमों में सरकार पक्षकार के होने के कारण सरकारी विभागों को कुशल वकील उपलब्ध करवाने व ऐसा व्यापक तंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनायी गयी जो विभागाध्यक्ष द्वारा अनावश्यक अपील को हतोत्साहित करेगा।

12. समाजवाद से क्या आशय हैं ?

उत्तरः– समाजवाद का आशय उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के संसाधनों पर सामुहिक स्वामित्व से है।

13. वर्तमान में श्रीलंका में राजनैतिक अस्थिरता का क्या कारण हैं ?

उत्तरः–प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (भारत के समर्थक) को बर्खास्त कर संसद भंग की व महिन्द्रा राजपक्षे (चीन के समर्थक) को प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बहुमत में नहीं होने से दोबारा चुनाव करवाने के प्रयास किये गये।

14. मूल अधिकारों की प्रकृति बताइयें ?

☞ मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं, प्रतिबंधों व अपवादों के साथ हैं।

☞ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात् अधिकारों का संरक्षण भी अधिकार हैं।

☞ नागरिकों व विदेशियों दोनों को उपलब्ध।

☞ विस्तृत अधिकार पत्र तीन पीढीयों के अधिकारों के रूप में (नागरिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक)।

15. 'अधिकार पृच्छा' की अवधारणा स्पष्ट करें ?

उत्तरः– किसी सार्वजनिक पद पर अवैध अधिकार को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली रीट अधिकार पृच्छा हैं।

16. भारतीय विदेश नीति की दो समकालीन विशेषताएँ लिखिए ?

☞ आर्थिक कूटनीति को महत्व (वैश्वीकरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी)

☞ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होना। (पहले पड़ौस नीति, सॉफ्ट पावर कूटनीति, कनेक्ट टू सेन्ट्रल एशिया इत्यादि)

17. जस्टिस गीता मित्तल में राज्य की भूमिका को प्रस्तुत करने वाले कोई दो उदाहरण लिखिए ?

उत्तरः– न्यायमूर्ति गीता मित्तल हाल ही में जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं।

18. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य की भूमिका को प्रस्तुत करने वाले कोई दो उदाहरण लिखिए?

☞ राज्यों द्वारा की जाने वाली ग्लोबल निवेश समिट (उदाहरण - वाइब्रेन्ट गुजरात, रिसर्जेन्ट राजस्थान)

☞ राज्यों द्वारा कृषि तकनिकों, जल संसाधनों के क्षेत्र में प्राप्त किया गया विदेशी सहयोग (उदाहरण - राजस्थान-इजराइल से कृषि तकनीक)

19. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से क्या आशय हैं ?

उत्तरः–यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ (आशियान) के 10 सदस्य राज्यों व 6 एशिया-प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हैं। भारत इसका सदस्य हैं।

20. 'सी-विजिल' हाल ही में कि संदर्भ में सुखियों में हैं?

उत्तरः–स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल एप सी.विजिल लॉंच किया है जिसके द्वारा आमजन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता हैं।

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50-50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित है।

21. संसदीय व अध्यक्षीय प्रणाली में अन्तर स्पष्ट कीजिए ?

संसदीय प्रणाली	अध्यक्षीय प्रणाली
☞ कार्यपालिका विधायिक के प्रति उत्तरदायी (समन्वय पर आधारित)	☞ कार्यपालिका, विधायिका में स्पष्ट पृथक्करण पर आधारित
☞ विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित	☞ विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति में निहित
☞ शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा	☞ शासन का नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा
☞ नीचला सदन राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता हैं।	☞ नीचला सदन राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता
☞ बहुदलीय व्यवस्था में अधिक उपयुक्त (विविधता का संरक्षण)	☞ द्विदलीय व परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपयुक्त
☞ नीतियों में निरंतरता का अभाव	☞ नीतियों में निरंतरता

22. "मूल कर्त्तव्य भारत की पुरातन संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं।" टिप्पणी कीजिए?

उत्तरः- मूल कर्त्तव्य भारतीय आदर्शों की संहिताबद्ध व्यवस्था हैं, जिन पर भारतीय सभ्यता व संस्कृति टिकी हुई हैं। 'सर्वे भवन्तु सुखिन' व वसुधैव कुटुम्बकम के विचार को मानववाद, समरता, भ्रातत्व एवं सामासिक संस्कृति जैसे शब्दों में स्थान प्राप्त हुआ हैं। 'अहिंसा परमोधर्म' का सिद्धांत प्रकृति के संरक्षण के रूप में पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण के मौलिक कर्त्तव्य में प्रकट होता हैं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते' पर आधारित नारी सम्मान, गरिमा व समानता को मूल कर्त्तव्यों द्वारा सुनिश्चित किया गया हैं। 'जननी जन्म भूमिश्च' की भावना देश की संप्रभुता, एकता की रक्षा व इसके प्रतीकों के सम्मान में परिलक्षित होती है। अतः मूल कर्त्तव्य द्वारा भारतीय पुरातन सांस्कृतिक विरासत को संविधान में व्यवस्थित स्थान दिया गया हैं।

23. अध्यादेश के संवैधानिक संदर्भ का तार्किक विवेचन कीजिए ?

उत्तरः- अनु. 123 व अनु. 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति व राज्यपाल की विधायी शक्ति के रूप में अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यदि उन्हें यह समाधान हो कि ऐसी परिस्थितिया विघमान है जिनमें तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित है व संसद के सत्रावसान के कारण कानून निर्माण संभव नहीं है। कूपरवाद (1971) में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर सीमाएँ लगाई गई हैं। अध्यादेश संसद की विधायी शक्ति का विकल्प नहीं है, अतः यदि सरकार संसद के विरोध से बचाव के लिए इसका सहारा लेती है व अध्यादेश पूर्वाग्रह, हटधर्मिता व असंबद्ध तथ्यों पर आधारित हो तो पुनरावलोकन संभव हैं।

24. न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ?

उत्तरः-अनु. 124(iv) व 217(i) न्यायाधीशों को पदच्युत करने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके तहत न्यायाधीशें को अक्षमता अथवा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता हैं। इन्हें हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है (लोकसभा 100 समर्थक व राज्यसभा 50 समर्थक)। प्रस्ताव आने पर संबंधित सदस्य के अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की जाती है व 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रतिवेदन पर चर्चा की जाती है व न्यायाधीश द्वारा अपना पक्ष रखा जाता है। यदि सदन कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों के $^{2}/_{3}$ बहुमत से प्रस्ताव पारित करें व दूसरा सदन उसी सत्र में प्रस्ताव स्वीकार करे तो न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाता हैं।

25. भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की दावेदारी का विश्लेषण कीजिए ?

दावेदारी का सकारात्मक पक्ष	दावेदारी में अवरोध
☞ भारत की जनसंख्या अधिक व सबसे बड़ा लोकतंत्र (संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिक चरित्र)	☞ अन्य स्थायी सदस्यों की तुलना में विकास में पीछे
☞ भारत तीसरे विश्व का नेतृत्वकर्त्ता है।	☞ शक्ति प्रदर्शन नहीं (विवाद का समाधान किस प्रकार)
☞ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत की सक्रिय भागीदारी	☞ क्षेत्रीय विवाद (चीन, पाकिस्तान)
☞ भारत की वैश्विक मुद्दों पर संवदेनशीलता(पर्यावरण, आतंकवाद आदि)	☞ आंतरिक समस्याएँ (अलगाववाद, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता आदि)
☞ अन्य संगठनों में सदस्यता	

26. "ग्राम सभा गाँव की संसद हैं।" टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः- संसद के समान ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का अनुमोदन किया जाता है व गाँव के विकास का नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्डसभा पर नियंत्रण, संरपच व पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षण, गाँव के बजट का प्रारूप तैयार करने जैसे कार्य ग्राम सभा को गाँव की संसद की उपमा देने हेतु पर्याप्त हैं। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त गाँव में शिक्षा को प्रोत्साहन व सामुदायिक सौहार्द में वृद्धि करने जैसे गुणात्मक कार्य भी ग्राम सभा द्वारा किये जाते हैं।

27. "प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को अभिव्यक्त करती हैं।" विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः- भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप रचित है जिसे शब्दशः प्रस्तावना संकल्पित करती है। न्याय के व्यापक अर्थों में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय को सम्मिलित किया गया है जो मूल अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों का आधार हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अंतिम स्त्रोत के 'भारत की जनता' हेतु समानता, स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व के वातावरण की परिकल्पना की गई है, साथ ही 'विविधता में एकता' की स्थापना हेतु 'अखण्ड राष्ट्र' की चेष्टा इस प्रकार की गई है जो संविधान को निर्देशित करता है। इस प्रकार प्रस्तावना, संविधान निर्माताओं के भावी भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब हैं।

28. भारत आसियान संबंधों पर टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः- बौद्ध धर्म व रामायण भारत व आसियान देशों को आपस में जोड़ते हैं। भारत-आसियान संबंधों ने हाल ही में 25 वर्ष पूर्ण किये हैं। आसियान देशों की जी.डी.पी. 28 हजार करोड़ से अधिक है इस दृष्टि से व्यापारिक हितों के लिए ये संबंध महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए आसियान चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार एवं पिछले दशकों में आसियान देश भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वृहद स्त्रोत रहे हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रतिद्वन्द्वी होने से ये देश भारत को चीन से प्रतिसंतुलन करने में सहायक है। भारत ने सहयोग को बढ़ाने के लिए साझा कोष बनाये है व भारत-म्यामार-थाईलैण्ड के बीच राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी हैं।

29. नागरिक समाज क्या हैं ? भारतीय राजनीति में इनका क्या महत्व है?

उत्तरः-नागरिक समाज संवेदनशाल बुद्धिजीवीयों व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का समूह है जो समाज व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण विषयों से सरोकार रखते हुए अन्तः क्रिया करते हैं। ये भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गये है। राजनीति के शुद्धिकरण पर्यावरण संरक्षण, लैगिंक उत्पीड़न की रोकथम, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण व नैतिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार से नागरिक समाज संबंधित है। व नागरिक समाज की गतिविधियाँ जनहित याचिकाओं के माध्यम से शासन-प्रशासन पर बाध्यकारी बन गई हैं। लोकपाल, लोक नीति, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार, विशाखा गाईडलाइन इत्यादि नागरिक समाज के कारण ही अस्तित्व में आयें।

30. 1998 के बाद से राजस्थान में द्विदलीय प्रणाली के अस्तित्व में आने के कारणों का विवेचन करें ?

- ☞ 1998 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कद बढ़ना।
- ☞ राजस्थान की राजनीति का राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक प्रभावित होना (जैसे 2003 में केन्द्र में एनडीए के प्रदर्शन के कारण राजस्थान में भाजपा, 2013 में केन्द्र में बड़े घोटाले उजागर होने के कारण कांगेस की राजस्थान में हार)।
- ☞ 2008 में भाजपा सरकार के सिद्धांत व व्यवहार में अंतर होना।
- ☞ राजस्थान में तीसरे मोर्चे का विकास न होना।
- ☞ राजनैतिक गत्यात्मकतओं की अवधि - जातिगत समीकरण, नगारिकों का जागरुक मतदान व्यवहार, वर्तमान सरकार की प्रवृत्तियाँ इत्यादि द्विदलीय प्रणाली के विकास के कारण हैं।

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित है।

31. न्यायिक सक्रियता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ?

उत्तरः- न्यायपालिका द्वारा कानूनी औपचारिक भूमिका से आगे बढ़कर तात्विक न्याय की स्थापना हेतु सार्वजनिक नीति पर विचार व्यक्त करना एवं निर्देश देना न्यायिक सक्रियता हैं। 1980 के दशक से न्यायिक नवाचार के तौर पर विधि की स्थापित प्रक्रिया में विधि की सम्यक प्रक्रिया का समावेश (संविधान की भावनात्मक व्याख्या पर बल) किया गया। इसके प्रारम्भिक चरणों में कैदियों की दशा में सुधार व उत्पीड़न से संरक्षण जैसे तत्व सम्मिलित हुए व तदुपरान्त गरिमामय जीवन का अधिकार, स्वस्थ

पर्यावरण, त्वरित न्याय की प्राप्ति खाद्य, पदार्थों में मिलावट से रोकथाम जैसे विषयों के शामिल होने से भारतीय लोकतंत्र लोक कल्याण स्वरूप में परिवर्तित हुआ।

इसी क्रम में न्यायिक सक्रियता के कारण पिछले तीन दशकों में कार्यपालिका व न्यायपालिका में टकराव उत्पन्न हुआ है। जनहित याचिकाओं की अधिक संख्या ने न्यायपालिका के कार्यों को बाधित किया है व जनहित याचिकाओं की अधिक संख्या ने न्यायपालिका के कार्यों को बाधित किया है, जनहित याचिकाएँ प्रसिद्धी का माध्यम बन गई है व इसे विरोध के लिए विरोध के काम में लिया जा रहा है। इस कारण न्यायिक अतिक्रमण की परिस्थिति बन रही है। अतः आवश्यक है कि न्याय पालिका से जिस संतुलन की अपेक्षा रखी जाती है, वह उस संतुलन को बनाये रखें।

32. राज्यसभा के द्वितीयय सदन के रूप में औचित्य परीक्षण करें ?

उत्तरः- राज्यसभा के अप्रत्यक्ष योगदान के कारण इस सदन के औचित्य पर यदा-कदा प्रश्न चिह्न लगते हैं। संघीय व्यवस्था में राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, साथ ही द्वितीय सदन के रूप में यह पुनरावलोकन का उत्तरदायित्व निभाती है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों व ऐसे व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहते है, उन्हें सत्ता तक लाने में राज्यसभा का विशेष महत्व हैं। कई महत्वपूर्ण संशोधन राज्यसभा में प्रस्तुत किये जाते है ताकि लोकसभा का विघटन होने पर व्यपगत न हो। साथ ही राज्यसभा पर आक्षेप लगाये जाते है कि यह विरोध के लिए विरोध वाला सदन है जिस कारण विधेयको के परित हाने में अनावश्यक देरी होती है। इसके अतिरिक्त यह उन व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वार है जिन्हें चुनाव में जनता नकार चुकी होती है। कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा के क्षेत्र से मनोनीत व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी कम ही दिखाई देती है। संघीय व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होते हुए भी क्षेत्रीय राजनीति से प्रभावित होती हैं व वित्तीय भार में भी अभिवृद्धि करती है किन्तु भारत की संघीय भावना के अनुरूप व सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में राज्यसभा द्वितीय सदन के रूप में नितान्त उपयोगी हैं।

33. 'चुनाव सुधार' पर लेख लिखिए ?

उत्तरः-भारत में चुनाव लोकतंत्र का उत्सव हैं किन्तु यह दोषपूर्ण दलीय व्यवस्था, वोट बैंक राजनीति, धनबल-भुजबल की घटनाओं व स्वस्थ प्रचार के अभाव जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहा है। इसमें सुधार के लिए तारकुण्डे समिति, गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, शेषन समिति व विधि आयोग की 170वीं व 255वीं रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं। भारत में चुनाव सुधार के तीन पक्ष हो सकते हैं। प्रथम-चुनाव प्रक्रिया में सुधार हेतु दलों के आय-व्यय का संपूर्ण विवरण, चुनाव में केवल सरकारी फंडिग, काला धन रोकने के अन्य उपाय, उम्मीदवारों की पूर्ण जानकारी, दागी होने की दशा में मीडिया में कम से कम तीन बार विज्ञापन, VVPAT का उपयोग, प्रत्याशियों के वाद का त्वरित निपटान, लोकसभा-विधानसभा का एक साथ चुनाव जैसे उपाय सम्मिलित हैं।

द्वितीय उपाय के रूप में चुनाव आयोग का सशक्तिकरण आवश्यक है, जिसमें आयोग को दाण्डिक शक्ति प्रदान करना, राजनैतिक दलों की मान्यता रद्द करने के संदर्भ में सशक्त करना सम्मिलित है। तृतीय उपाय मतदान व्यवहार में सुधार द्वारा किया जा सकता है जिसमें जागरूकता अभियान, ऑन लाइन वॉटिग, स्वतः मतदाता पंजीकरण, मतदान दिवस के दिन पंजीकरण, दुरूस्त परिवहन व्यवस्था इत्यादि महत्वपूर्ण है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विगत सात दशकों से निरन्तरता भारत में चुनाव का पर्याप्त महत्व व सफलता प्रदर्शित करती है, इसे अधिक दक्ष बनाने के लिए उपर्युक्त संदर्भ में प्रयास अपेक्षित है।

34. 'BIMSTEC' की भारत के लिए प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए ?

उत्तरः- 1997 (बेकॉक घोषणा) से अस्तित्व में आये बिम्सटेक संगठन में वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती 7 राष्ट्र (भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैण्ड, म्यामार, नेपाल व भूटान) सम्मिलित हैं। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य तकनीकी व आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना हैं। वर्तमान में सहयोग के 16 क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं जिनमें से 4 क्षेत्रों (पर्यटन, पर्यावरण व आपदा प्रबंधन, आंतकवाद व अन्तर्राष्ट्रीय अपराध एवं परिवहन-संचार) के नेतृत्व की जिम्मेदारी भारत को दी गई हैं। उक्त वर्णित सहयोग के अतिरिक्त बिम्सटेक सार्क के अस्तित्व पर संकट के दौर में वैकल्पिक संगठन के रूप में कार्य कर सकता है, जो भारत की पाकिस्तान को अलग-थलग करने की नीति का हिस्सा हैं। व्यापारिक महत्व के अतिरिक्त यह संगठन दक्षिण एशिया व दक्षिण-पूर्वी एशिया के मध्य सेतु का कार्य करता हैं, थाईलैण्ड, म्यांमार, के माध्यम से भारत आसियान से निकटता स्थापित कर सकता है। साथ पूर्वोत्तर राज्यों के विकास व शांति में सदस्य राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता हैं। बिम्सटेक की प्रासंगिकता को दृष्टिगोचर करते हुए ही भारत ने 2020 में अन्तराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की हैं।

35. अनुच्छेद 35(A) के संबंध में क्य विवाद हैं ?

उत्तरः–अनुच्छेद 35(A) जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह विशेषाधिकार देता है कि वह 'स्थायी निवासी' को परिभाषित कर सके। स्थायी निवासियों को ही जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने या मतदान करने की अनुमति हैं। इनसे इतर सभी व्यक्तियों को संपत्ति खरीद, स्थायी रूप से बसने व राज्य की सरकारी नैकरी के लिए आवेदन करने का निषेध किया गया हैं। इस अनुच्छेद को न्यायालय में एक एन.जी.ओ. द्वारा मूल अधिकारों का हनन मानते हुए चुनौती दी गई हैं। इसे महिलाओं के प्रति पक्षपाती माना गया है, क्योंकि महिलाओं द्वारा गैर–स्थायी निवासी से विवाह करने पर उसके अधिकार महिला के पति व बच्चों को स्थानान्तरित नहीं होते। इस संदर्भ में एक अन्य विवाद इस अनुच्छेद को जोड़े जाने की प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि इसे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया है न कि अनुच्छेद 368 की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा इस अनुच्छेद के कारण कुछ समुदाय विशेष (गोरखा, सिख इत्यादि) के लोगों को कई वर्षों से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है व यह मानसिक अलगाव को प्रोत्साहित करता है, किन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि 35(A) को समाप्त करने से जम्मू–कश्मीर का जनाकिंकीय परिदृश्य परिवर्तित हो सकता है एवं राज्य की स्वायत्तता जो कि विलय की शर्तें थी, (विलय एवं राज्य की विशेष स्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं) में कमी आयेगी। अतः इसे वर्तमान परिस्थितियों में समाप्त नहीं करना चाहिए।

सारथि एकेडमी